मौद्रिक नीति ओर आर्थिक विकास

डा. अंजू अग्रवाल

एम. ए {अर्थशास्त्र}

पी. एच. डी.

वर्तमान में राष्ट्रों के विकास कामापदंड उनकी आर्थिक स्थिति है। अर्थव्यवस्था की सुद्रढता क्षमता और गहनता एक बड़ी सीमात कमौद्रिक नीति की सफलता पर निर्भर करती है। अतः मौद्रिक नीति ओर आर्थिक विकास परस्पर पर्याय बन गए हैं। मौद्रिक नीति देश की मौद्रिक प्रणाली से संचालित होती है ओर इसका संबंध उन सभी उपायों तथा निर्णयों से होता है, जो मौदिक स्वभाव के होते हैं। मौद्रिक नीति मौद्रिक क्षेत्र में सरकार की आर्थिक नीति है, जिसे देश का केंद्रीय बैंक क्रिया न्वित करता है।

मौद्रिक नीति का उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, जो विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर भिन्न–भिन्न होते हैं। ये उद्देश्य देश के आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। कभी कभी यह उद्देश्य परस्पर विरोधी होने के साथ–साथ कई कार को से भी प्रभावित होते हैं। मौलिक रुप सेमोद्रिक नीतिका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली से उत्पन्न होने वाले लाभों को अधिकतम करना तथा हानियों को न्यूनतम करना होता है, इसक लिए मोध्रिक नीति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की पूर्ति या तरलता को प्रभावित कर के निरंतर समा योजन करती है। इसीलिए यह सच ही कहा गया है कि मौद्रिक नीति स्वयं में कोई साध्य ना होकर के वास्तव में कुछ निश्चित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है।

भारत है सेविका सशील देश में मौद्रिक नीतिका उद्देश्य आर्थिक वकास के साथ–साथ कीमत स्थिरता को भी प्राप्त करना होता है ताकि मूल्य उच्चा वन का आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव ना पड़े मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने हेतु केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की विभिन्न परिमानणात्मक एवं गुणात्मक नीतियां प्रयोग करता है। वर्तमान समय में यह अनुभव किया जा रहा है कि इन विधियों को प्रभाव शीलता अनेक बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप तथा अर्थव्य वस्था के आंतरिक ढांचे में परिवर्तन के कारण सीमित होती जा रही यह बाहरी तत्वः–

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की उपलब्ध्ता की शर्तें
- विदेशी पूंजी का आगमन
- विदेशी मुद्रा भंडार में आशातीत वृद्धि
- वित्तीय क्षेत्र का अंत र्राष्ट्रीय करण

- शक्तिशाली राष्ट्रों का दबाव

के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यह देखा जा रहा है कि विगत कुछ समय से निश्चय हीभारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है तथा देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में अनेक केंद्रीय परिवर्तन हुए हैं।स्वरूप बजट घाटा ही स्फीतिकारी प्रवृतियों के लिए उत्तरदायी नहीं है तथा केवल इस को ही नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। आह के बदलते हुए राष्ट्रीय तथा अंत राष्ट्रीय परिवेश में एक व्यवहारिक मौद्रिक नीति का निमाँण तथा न्रियान्वन अत्यंत आवश्यक है जिस सेदेश के हितों की रक्षा हो सके।

देश में मौद्रिक नीति का संचालन रिर्जव बैंक की स्थापना से ही होता आया है तथा समय–समय पर इस संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय ढांचे में अनेक परिवर्तन भी आए हैं और उस पर अनेक बाहरी तत्वों का प्रभाव भी दृष्टि गोचर होता है। वित्तीय ढांचे में आए परिवर्तन तथा आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप न केवल उदारी करण तथा वैश्यी करण की प्रक्रिया को बल मिला है अपितु परिवर्तित होते हुए परिवेश में मौद्रिक नीति के नए आयाम भी विकसित हुए हैं जिनका मौद्रिक नीति में समावेश तथा समायोजन आवश्यक है जिससे परिवर्तित होते हुए वातावरण में मौद्रिक नीति की सार्थकता को सिद्ध किया जा सके।

- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सकंट
- विदेशी पूंजी पर निर्भता
- रूपए कानिरंतरगिताहुआमूल्य
- वित्तीय बाजार को अधिकम जबीत बनाने की आवष्यकता
- मुद्रास्फीती
- रूपए की पुंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता
- बढता हुआ राज कोषीय घाटा
- औदयौगिकमंदी

जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक ऐसी मौद्रिक नीति की आवश्यकता है जिससे वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का सफतला पूर्वक सामना किया जा सके।

वर्तमान परिपेक्षय मेंमुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के स्थान पर मुद्रा पूर्ति की व्यवस्था अधिक आवश्यक है इसीलिए बदलती हुई परिस्थितियों में एक ऐसी मौद्रिक नीति की आवश्यकता है जिसम अधिक गहनता होताँ जो सामंजस्यपूर्ण हो क्योंकि कोई भी मौद्रिक नीति जो कीमतस्तर में स्थिरताला सकती है तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि कर सकती है वह निश्चित रूप से आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होती है। इसीलिए रिजर्व बैंक को उसके संचालन के स्तर पर अधिक

स्वायत्तता दी जानी चाहिए तथा मौद्रिक नीति के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य किया जाना चाहिए जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके।